भारत की आकांक्षाओं का वित्तपोषण

माइकल देवब्रत पात्र

नमस्कार! सुप्रभात,

आज यहाँ आकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। सीआईआई द्वारा आयोजित यह पहल - वित्त पोषण 3.0 पर शिखर सम्मेलन - शायद अपनी तरह की पहली पहल है और यह वर्तमान समय में महत्व रखती है, क्योंकि यह भारत के भविष्य की ओर छलांग लगाने वाले प्रकाश स्तंभ के रूप में अपनी स्थिति बना रही है। इसलिए, सबसे पहले, मैं 1895 से भारत के औद्योगिक और व्यावसायिक परिदृश्य को आकार देने में सीआईआई की भूमिका की भूरी-भूरी सराहना करना चाहूँगा, जो आज देश में सबसे अधिक दिखाई देने वाला व्यावसायिक संगठन है। यह उचित ही है कि मैं एक राष्ट्र के रूप में हमारी महत्वाकांक्षाओं और उन्हें साकार करने में वित्त की भूमिका पर विचार करके सीआईआई के असाधारण योगदान को अभिनंदन अर्पित करूँ।

II. भारत का एक आकांक्षापूर्ण दृष्टिकोण

राष्ट्र के भाव में स्पष्ट स्पंदन है। व्यापक रूप से ऐसा माना जा रहा है कि यह भारत की सदी है। प्रत्येक भारतीय के लिए दुनिया में सर्वोत्तम जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाले मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अवसर की एक खिड़की खुल गई है । शास्त्रीय अर्थशास्त्र की परंपरा में, यह माना जाता है कि उत्पादक कार्यबल ही मूल्य निर्माण का सच्चा स्रोत है; पूंजी केवल आयोजन कारक है, जो श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है और इसके विकास के लिए परिस्थितियां बनाती है। अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष के उस शास्त्रीय अर्थ में, दुनिया का हर छठा कामकाजी व्यक्ति एक भारतीय है, जो दुनिया की सबसे युवा आबादी होने का लाभ उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत की कामकाजी आयु वाली आबादी प्रति वर्ष 9.7 मिलियन बढ़ेगी।[1] 2030 तक उक्त समूह के कुल आबादी का 68.9 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है।[2]

मांग पक्ष की ओर से, भारत इस बढ़ते कार्यबल को तीव्र गति से कौशल प्रदान करेगा, यह देखते हुए कि हम पहले से ही दुनिया में सबसे अधिक संख्या में एसटीईएम[3] स्नातक तैयार कर रहे हैं – हर साल 20 लाख से अधिक, जिनमें से 43 प्रतिशत महिलाएं हैं[4]। भारत डिजिटल क्रांति में भी सबसे आगे है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में और स्टार्ट-अप पारितंत्र में दुनिया के नेतृत्वकर्ताओं में से एक है। अनुमान बताते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकती है[5]। जैसे-जैसे वैश्विक विनिर्माण केंद्र और निर्यात महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा साकार होती है, कार्यशील आयु वाली आबादी की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और भारत में आय और समृद्धि बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में अर्थशास्त्रियों ने दिखाया है कि जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने से अगले दो दशकों में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि में प्रति वर्ष लगभग 2 प्रतिशत अंक की वृद्धि हो सकती है।[6] वास्तव में, हालिया शोध जनसांख्यिकी लाभांश, डिजिटल नवाचार और आर्थिक विकास के बीच संबंधों की पुष्टि करता है[7]। भारत के कामकाजी आयु अनुपात में वृद्धि के साथ जुड़ी उच्च बचत और निवेश दरों द्वारा समर्थित, आज के जीडीपी स्तरों और 2047 के बीच यात्रा करना संभव हो जाएगा, जैसा कि हाल ही में नीति आयोग[8] द्वारा परिकल्पित किया गया है और एक उन्नत अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रति व्यक्ति आय स्तरों को पार करना संभव हो जाएगा। काल-चर दृष्टिकोण से, लगभग एक दशक के लिए गति का तीव्र होना आवश्यक है; उसके बाद, विशुद्ध गति भारत को कम विकास दर पर भी आगे बढ़ाएगी। इस रास्ते पर, हमें एक हरित, स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, नवाचार ऊर्जा को उन्मुक्त करने के लिए विश्व स्तरीय

* 2024 को मुंबई, भारत में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित वित्तीयन 3.0 शिखर सम्मेलन: विकसित भारत की तैयारी में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के उप गवर्नर माइकल देवब्रत पात्र द्वारा दिया गया मुख्य भाषण । सुनील कुमार, स्नेहल एस हेरवाडकर, समीर रंजन बेहरा, धन्या वी, राजस सरौए, संभावी ढींगरा, गौतम से प्राप्त मूल्यवान टिप्पणियों और विनीत कुमार श्रीवास्तव से प्राप्त संपादकीय सहायता के लिए आभार।

[1] भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19, खंड 1, अध्याय 7।

[2] अन्र्स्ट एंड यंग, 2023, इंडिया@100: रीपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड, 11 अप्रैल।

[3] विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम)।

[4] भारत सरकार, अंतरिम केंद्रीय बजट, 2024-25।

[5] विदेश मंत्रालय, 2020, भारत ने बीएफएसआई क्षेत्र में एआई नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए हब लॉन्च किया।

[6] अय्यर, एस. और मोदी , ए., 2011, जनसांख्यिकी लाभांश: भारतीय राज्यों से साक्ष्य, आईएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यूपी/11/38।

[7] ज़मान, के.ए., यू. और सरकार, टी., 2021, जनसांख्यिकी लाभांश, डिजिटल नवोन्मेष और आर्थिक विकास: बांग्लादेश अनुभव, एशियाई विकास बैंक संस्थान वर्किंग पेपर 1237।

[8] आज की 3.36 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी से 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना तथा प्रति व्यक्ति आय आज की 2,392 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से बढ़कर 18,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष होना (नीति आयोग, 2047 के लिए विकसित भारत का विजन-एक दृष्टिकोण पत्र, 7 अगस्त, 2024)।

भौतिक अवसंरचना और अनुकूल वातावरण का निर्माण करने की आवश्यकता होगी। भारत मानवता के लिए एक न्यायसंगत, समावेशी और सुदृढ़ भविष्य प्राप्त करने के लिए विश्व व्यवस्था को नया रूप देने में भी योगदान देगा।

III. वित्त और विकास पर पुनर्विचार

'कल के भारत' के इस विजन को पूरा करने की कुंजी वित्त की भूमिका है। विकास और वित्त के बीच संबंधों पर वर्षों से एक जीवंत बहस चल रही है। अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि यह या तो आपूर्ति चालित या मांग के अनुक्रम का अनुसरण करता है। पहली स्थिति में, वित्तीय क्षेत्र का विकास आर्थिक विकास से पहले होता है। उदाहरण के लिए, किसी देश के आर्थिक आकार के सापेक्ष वित्तीय क्षेत्र की गहराई या आकार को भविष्य के आर्थिक विकास, भौतिक पूंजी संचय और आर्थिक दक्षता में सुधार का एक मजबूत भविष्य वक्ता माना जाता है।[9] दूसरी स्थिति में, यह माना जाता है कि अर्थव्यवस्था का विकास होना चाहिए और फिर वित्तीय क्षेत्र को उसका अनुसरण करना चाहिए। साथ ही, यह मान्यता है कि यह संबंध सभी देशों और अवधियों में रैखिक नहीं हो सकता है। विकास के अपेक्षाकृत कम स्तरों पर, यह पारस्परिक रूप से सुदृढ़ अनुक्रम परिवर्तनकारी हो सकता है, लेकिन विकास के उच्च स्तरों पर कम प्रभावी हो सकता है।[10] अंतर्जात विकास सिद्धांत में प्रगति दोनों परिकल्पनाओं का समर्थन करती है, नवाचार और शिक्षा में निवेश को सुविधाजनक बनाने, लेनदेन लागत को कम करने और जोखिमों का प्रबंधन करने में वित्त और वित्तीय मध्यस्थों की भूमिका पर जोर देती है, जिससे विकास प्रक्रिया में तेजी आती है।[11]

वास्तविकता यह है कि दोनों धागे आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। जहाँ, एक अच्छी तरह से काम करने वाला वित्तीय क्षेत्र संसाधनों के कुशल आवंटन और अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता के दोहन के लिए एक पूर्व शर्त है, वहीं, यह भी स्वयंसिद्ध है कि वित्तीय सेवाओं की मांग विकास और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के औपचारिककरण पर निर्भर करती है। दूसरी ओर, व्यापार और वित्तीय चक्र एक दूसरे को पोषण, सुदृढ़ और प्रवर्धित करते हैं। इसमें आगे और पीछे भी होते हैं। अगस्त की शुरुआत में, हमने दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में बेतहाशा गिरावट देखी – जो 1987 के काले सोमवार (ब्लैक मंडे) की याद दिलाता है - जब आने वाले डेटा को आसन्न मंदी के संकेत के रूप में पढ़ा गया, जिससे व्यापक रूप से बिकवाली हुई और बिकवाली जारी रखने (कैरी ट्रेड) की वैश्विक समाप्ति हुई। इसी तरह, यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर वैश्विक मुद्रास्फीति में उछाल ने मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थितियों में एक समन्वित और आक्रामक कठोरता को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2023 में कुछ क्षेत्राधिकारों में बैंक विफलताएं और जमा राशि में कमी आई।

IV. राष्ट्रीय लेखांकन में वित्त को स्थान देना

आय और व्यय के चक्रीय प्रवाह में जो अर्थव्यवस्था के कामकाज का वर्णन करता है, वस्तुओं, सेवाओं, मुआवज़ों और करों में लेन-देन बचत और निवेश के प्रवाह से मेल खाते हैं, जो उधार देने योग्य संसाधनों के अंतर-क्षेत्रीय हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में, घरेलू क्षेत्र आमतौर पर अपने निवेश के सापेक्ष अधिशेष बचत उत्पन्न करता है जिसे वह अन्य क्षेत्रों को उधार देता है। हाल ही में, महामारी के दौरान संचित विवेकपूर्ण बचत को समाप्त करने के साथ-साथ वित्तीय आस्तियों से आवास जैसी भौतिक आस्तियों में बदलाव के रूप में चल रहे व्यावहारिक परिवर्तनों के कारण परिवारों की निवल वित्तीय बचत 2020-21 के स्तर से लगभग आधी हो गई है। आगे चलकर, बढ़ती आय से प्रेरित होकर, परिवार अपनी वित्तीय आस्तियों का फिर से निर्माण करेंगे - 2000 के दशक की शुरुआत से लेकर वैश्विक वित्तीय संकट तक यह सकल घरेलू उत्पाद का 15 प्रतिशत रहा था। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है - परिवारों की वित्तीय आस्तियां 2011-17 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 10.6 प्रतिशत से बढ़कर 2017-23 (महामारी वर्ष को छोड़कर) के दौरान 11.5 प्रतिशत हो गई हैं। महामारी के बाद के वर्षों में उनकी भौतिक बचत भी सकल घरेलू उत्पाद के 12 प्रतिशत से अधिक हो गई है और आगे भी बढ़ सकती है – यह 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद

[9] किंग, आर.जी. और लेविन, आर. (1993). वित्त और विकास: शुम्पीटर सही हो सकते हैं. क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स 108(3), 717-737; लेविन, आर. और ज़र्वोस , एस. (1998). शेयर बाजार, बैंक और आर्थिक विकास. अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू 88(3), 537-558.

[10] हुआंग, एच. और लिन, एस. (2009)। नॉन-लीनियर फाइनेंस-ग्रोथ नेक्सस। संक्रमण का अर्थशास्त्र 17(3), 439-466।

[11] लेविन, आर., (2004). वित्त और विकास: सिद्धांत और साक्ष्य, एनबीईआर वर्किंग पेपर नंबर 10766; रोमर, पीएम, (1990). अंतर्जात तकनीकी परिवर्तन, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 98(5, भाग 2), एस71-एस102.

के 16 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। तदनुसार, आने वाले दशकों में परिवार शेष अर्थव्यवस्था के लिए शीर्ष निवल ऋणदाता बने रहेंगे। निजी कॉरपोरेट क्षेत्र ने शेष अर्थव्यवस्था से अपने निवल उधार को काफी कम कर दिया है[12], जो बढ़ती आंतरिक प्राप्ति और मंद क्षमता निर्माण के संयोजन को दर्शाता है। आगे देखते हुए, कैपेक्स चक्र में पुनरुद्धार के पीछे इसकी निवल उधारी आवश्यकता बढ़ने की संभावना है। इन वित्तपोषण आवश्यकताओं को बड़े पैमाने पर परिवारों और बाहरी संसाधनों द्वारा पूरा किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की निवल बचत असमान रूप से कम हो रही है; भारत के भविष्य को आकार देने में राजकोषीय नीति के लिए परिकल्पित महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में निवल उधारकर्ता बना रहेगा।

पूरे देश में घाटा है, तो वह बाकी दुनिया से उधार लेता है और विदेशी बचत का प्रवाह उसकी निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। भारत के लिए, घरेलू बचत ने विकास की समग्र निवेश आवश्यकताओं को काफी हद तक वित्तपोषित किया है, जिसमें बाहरी वित्तपोषण ने एक पूरक भूमिका निभाई है, जैसा कि काफी हद तक मामूली चालू खाता घाटे में परिलक्षित होता है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता बढ़ती है और विदेशी संसाधनों को अवशोषित करने की इसकी क्षमता बढ़ती है, बाहरी वित्तपोषण की मात्रा और इसकी संरचना में मौलिक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन पिछले अनुभवों के आलोक में, बाहरी ऋण स्थिरता एक नीतिगत प्राथमिकता बनी रहेगी।

कार्यबल और उसकी मितव्ययिता और उत्पादकता सहित प्राकृतिक संपदा को देखते हुए, यह निवेश की दर है जो अर्थव्यवस्था के विकास पथ के साथ-साथ इसके संरचनात्मक बदलावों में महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान करती है। जैसा कि पहले बताया गया है, अर्थव्यवस्था अपने दृष्टिकोण की खोज में आधुनिक होती जा रही है, बाजार वित्तपोषण के विस्तार और परिष्कार में वृद्धि होने की संभावना है। वित्तीय मध्यस्थता की संस्थागत संरचना विशेषज्ञता के क्षेत्रों का दोहन करते हुए और तकनीकी समाधानों का लाभ उठाते हुए अधिक विविध हो सकती है।

ऐतिहासिक रूप से, भारत में विकास में तेजी के चरणों के साथ-साथ सकल घरेलू निवेश दर भी बढ़ी है। विकास की समग्र दर के अलावा, वांछित निवेश दर का एक प्रमुख निर्धारक जीडीपी की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी की इकाइयों की संख्या के संदर्भ में पूंजी उपयोग की दक्षता है। यह वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) जितना कम होगा, पूंजी की उत्पादकता या पूंजी की सीमांत दक्षता उतनी ही अधिक होगी। अधिकांश विकसित देशों में आईसीओआर 3 के आसपास है। 2012-19 की अवधि में, भारत में आईसीओआर औसतन 5.0 था, लेकिन पिछले तीन वर्षों में यह 4.0 पर आ गया है। जैसे-जैसे ये दक्षता लाभ बढ़ते हैं, कार्यबल कौशल हासिल करता है और आर्थिक संरचना परिष्कार और तकनीकी प्रगति हासिल करती है, आईसीओआर को 3.5 से 4 की सीमा में परिकल्पित करना संभव है। तदनुसार, उच्च विकास के एक दशक में आवश्यक निवेश प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 33-38 प्रतिशत के दायरे में होगा। यह किसी भी तरह से असंभव नहीं है, अगर 2010-11 में हासिल की गई लगभग 39 प्रतिशत की ऊंचाई को संभावित माना जाए। जीडीपी के 32-36 प्रतिशत की सीमा में बचत दरों के साथ इस वांछित निवेश दर को वित्तपोषित करना संभव है, जो 2007-08 में हासिल की गई 37.8 प्रतिशत की ऊंचाई को देखते हुए फिर से प्राप्त करने योग्य है।[13] भविष्य की ओर देखते हुए, यह आकांक्षा सभी प्रमुख घटकों - बढ़ते कुशल कार्यबल के बल पर परिवार; विनिर्माण और निर्यात पर जोर से लाभान्वित होने वाले व्यवसाय; और वर्तमान मजबूती को जारी रखने वाली सरकारों के बीच बचत क्षमता में सुधार पर आधारित है। जैसा कि पहले कहा गया है, बाहरी वित्तपोषण का योगदान परिमाण और संरचना को बदल सकता है।

मैं आशा करता हूँ कि अपने शेष संबोधन में मैं भारत के आकांक्षात्मक लक्ष्यों में वित्त के विकासात्मक योगदान के कुछ रणनीतिक पहलुओं पर नजर डालने के लिए उपलब्ध अनुमानों का उपयोग कर सकूंगा।

V. अवसंरचना

अवसंरचना राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवसंरचना पर खर्च पूंजीगत व्यय के वर्ष में 2.45 और अगले

[12] वर्ष 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत से घटकर हाल ही में 1 प्रतिशत से भी कम हो गया है।

[13] नीति आयोग की नवंबर 2018 की "नया भारत @75 के लिए रणनीति" में भी इसी तरह की आकांक्षा व्यक्त की गई है।

वर्ष में 3.14 का जीडीपी गुणक उत्पन्न करता है।[14] सालाना जीडीपी के कम से कम 8-10 प्रतिशत की अवसंरचना में निवेश की आवश्यकता के साथ[15], भारत का अवसंरचना अंतर प्रति वर्ष जीडीपी का 4.1 प्रतिशत अनुमानित किया गया है, जो जलवायु आवश्यकताओं के लिए समायोजित होने पर 5.3 प्रतिशत हो जाता है।[16] 2024-30 की अवधि में, यह अनुमान लगाया गया है कि अवसंरचना में निवेश को 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (143 लाख करोड़ रुपये) तक बढ़ाना होगा, जिसमें लगभग 0.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हरित निवेश होगा।[17] भविष्य में निजी क्षेत्र अवसंरचना व्यय के, विशेष रूप से, ऊर्जा और परिवहन में, केंद्र में आ जाएगा। वित्तपोषण के स्रोत विविध होंगे, जिनमें घरेलू पूंजी बाजार में ऋण और इक्विटी जारी करने से लेकर बाह्य वाणिज्यिक उधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तक शामिल होंगे।

VI. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं - यह अनुमान लगाया गया है कि एमएसएमई क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत, निर्यात का 45 प्रतिशत और व्यापार क्षेत्र में 62 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है।[18] आने वाले वर्षों में एमएसएमई की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत के एमएसएमई की कुल वित्त मांग लगभग 1,955 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसमें से ऋण आधारित वित्त की मांग 1,544 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है,[19] जिनमें से आधी उन लोगों से आती है जो अनौपचारिक स्रोतों से या वित्तीय रूप से अलाभकारी उद्यमों से वित्तपोषण पसंद करते हैं। इससे 819 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण मांग बचती है, जिसमें से 289 अरब अमेरिकी डॉलर की मांग वर्तमान में बैंकों जैसे औपचारिक ऋणदाता द्वारा पूरी की जाती है। शेष 530 बिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष मांग बैंकों, फिनटेक और एनबीएफसी के लिए एक विशाल बाजार बनाती है।

VII. कौशल विकास

भविष्य के लिए तैयार होने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जिसमें तकनीकी परिवर्तन में तेजी के अनुरूप मानव संसाधनों को कुशल बनाना प्रमुख रूप से शामिल है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, अगले पांच वर्षों में वैश्विक स्तर पर 44 प्रतिशत श्रमिकों के कौशल में व्यवधान आएगा।[20] भविष्य के कार्यबल को प्रभावी ढंग से कुशल बनाने के लिए, भारत को अगले 6 वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 2-3 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की आवश्यकता है।[21] इसमें अवसंरचना, प्रशिक्षण केंद्र और निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी शामिल होगी।

कौशल आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने में प्रदर्शन-आधारित निवेश साधनों जैसे कि पूर्व-सहमत सामाजिक परिणाम के साथ विकास कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से बांड, मजदूरी रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने वाले मोचनीय कौशल वाउचर, तकनीक-आधारित प्रशिक्षण प्लेटफार्मों, ई-लर्निंग स्टार्ट-अप और इस तरह के लिए निजी इक्विटी/उद्यम पूंजी निधि, सामाजिक विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के रूप में बहुपक्षीय एजेंसियों, सामाजिक और निजी संगठनों से प्रत्यक्ष समर्थन; और कार्यशील पूंजी वित्तपोषण, प्रशिक्षुओं और सेवा प्रदाताओं को संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों के साथ समझौतों में व्यापार प्राप्तियां छूट प्रणाली को जोड़ा जा सकता है।[22] केंद्रीय बजट 2024-25 ने श्रम बल को कुशल बनाने में निजी क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका पर ज़ोर दिया है। अब तक केवल 36 प्रतिशत कंपनियां उद्यम-आधारित प्रशिक्षण आयोजित करती हैं।[23] शीर्ष 500 कंपनियों में युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसरों की सुविधा के लिए बजट प्रस्ताव से उद्योगों की कौशल मांग को पूरा करने के साथ-साथ श्रम बल के लिए कौशल अवसर बढ़ सकते हैं।

---

[14] राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2022-23 पर चर्चा, 11 फरवरी, 2022; बोस, एस. और भानुमूर्ति , एनआर, 2015, भारत के लिए राजकोषीय गुणक। मार्जिन: जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च 9(4), 379-401।

[15] आरबीआई के आंतरिक अनुमान।

[16] एशियाई विकास बैंक, 2017, एशिया की अवसंरचना संबंधी जरूरतों को पूरा करना, 1 फरवरी।

[17] क्रिसिल (2023)। वित्त वर्ष 2024 और 2030 के बीच भारत का अवसंरचना व्यय 2017-2023 की तुलना में दोगुना होकर ₹143 लाख करोड़ हो जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति। 17 अक्टूबर।

[18] भारत सरकार, असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई), 2022-23; पीआईबी, 2023, देश के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का योगदान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। 11 दिसंबर; मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट, 2024, छोटे व्यवसायों पर एक सूक्ष्म विश्लेषण: देश के अनुसार उत्पादकता अवसर, मई।

[19] एवेंडस , 2023, एमएसएमई ऋण: क्षमता को खोलना, सपनों को साकार करना, अप्रैल।

[20] विश्व आर्थिक मंच, 2023, नौकरियों का भविष्य रिपोर्ट, मई।

[21] आरबीआई के आंतरिक अनुमान।

[22] केपीएमजी-फिक्की, 2023, भारत में कौशल वित्तपोषण, सितंबर।

[23] अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, 2024, भारत की रोजगार रिपोर्ट 2024: युवा रोजगार, शिक्षा और कौशल।

VIII. जलवायु

जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने के लिए 2024-2030 की अवधि में ₹30 लाख करोड़ (यूएस$ 0.36 ट्रिलियन) के निवेश की आवश्यकता होगी।[24, 25] प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य वाले भारत के 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' में ₹19,744 करोड़ या 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रारंभिक परिव्यय शामिल होगा।[26] इसके अलावा, 2047 तक जीवाश्म ईंधन के आयात से मुक्त होने और 2070 तक निवल शून्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 10.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण की आवश्यकता होने का अनुमान है।[27]

हाल के अनुभव के आधार पर, सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) का उपयोग ग्रीन परियोजनाओं को वित्तपोषित या पुनर्वित्तपोषित करने के लिए किया जा सकता है। एसजीआरबी वैश्विक रूप से गतिशील पर्यावरण, स्थिरता और अभिशासन (ईएसजी) निधियों को जुटाने के लिए निजी उद्यम द्वारा ग्रीन बॉण्ड के मूल्य निर्धारण के लिए एक बेंचमार्क भी प्रदान कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत एक निश्चित सीमा तक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को शामिल करने और "हरित जमा की स्वीकृति के लिए रूपरेखा" से हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए बैंक निधीयन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही, जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों पर आरबीआई का मसौदा प्रकटीकरण रूपरेखा अपर्याप्त जानकारी के कारण आस्तियों के गलत स्थान पर रखे जाने और पूंजी के गलत आवंटन को रोकने की दिशा में काम करेगा। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई और स्वचालित मार्ग के तहत हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटाने वाली कंपनियों के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार के लिए शिथिल मानदंडों के साथ, एक बार हरित वर्गीकरण विकसित होने और वैश्विक मानकों के साथ संरेखित होने के बाद, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों जलवायु वित्त का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है।

IX. डिजिटलीकरण

भारत में तेजी से डिजिटल बदलाव हो रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल बैंकिंग ऐप और ऑनलाइन सेवाएँ नकदी निर्भरता को कम कर रही हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही हैं। कई फिनटेक कंपनियाँ और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म व्यक्तियों और व्यवसायों को त्वरित और परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करते हैं, जो क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और एआई का उपयोग करते हैं।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की सफलता एक गेम-चेंजर रही है, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों में से एक बनाती है। अन्य विकासों में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) परियोजना या e₹ शामिल है, जिसमें न केवल भुगतान परिदृश्य, बल्कि व्यापक वित्तीय प्रणाली को बदलने की क्षमता है। डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस (डीएससीएफ) एक और उभरता हुआ खंड है जो डिजिटल वित्तीय सेवाओं को आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने, सुगम लेनदेन की सुविधा, जोखिम को कम करने और समग्र दक्षता को बढ़ाने का प्रयास करता है। बीमा, पूंजी बाजार और ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के विस्तार में भी डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, भारत 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बन सकता है, जिसमें डिजिटल वित्तपोषण की आवश्यकता सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.3 प्रतिशत होगी।[28] इस निकट-अवधि लक्ष्य से अनुमान लगाते हुए, 2047 में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार 5.4 से 6.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच होगा, और डिजिटल बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण का अंतर 2047 तक लगभग 124-159 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।[29]

---

[24] पीआईबी, 2024: "भारत को अपने सीओपी जलवायु प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2024-2030 के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है", विश्व बैंक वेबिनार में आईआरईडीए के सीएमडी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 15 फरवरी।

[25] यह निवेश सौर फोटोवोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोलाइजर, पवन ऊर्जा उपकरण, बैटरी ट्रांसमिशन और अपशिष्ट को ऊर्जा में रूपान्तरण के लिए विनिर्माण क्षमता में आवश्यक होगा।

[26] पीआईबी, 2023, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 3 जनवरी।

[27] ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (2021)। भारत के 2070 निवल शून्य लक्ष्य के लिए निवेश का आकार। 18 नवंबर।

[28] भारत को डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग और बढ़ते ऑनलाइन ट्रैफ़िक का समर्थन करने के लिए भौतिक डिजिटल अवसंरचना में 2025 तक 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के निवेश की आवश्यकता है (अर्नस्ट एंड यंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (2022)। डिजिटल इंफ्रा कंपनी - अनलॉकिंग द टावर पावर। जनवरी)।

[29] आरबीआई के आंतरिक अनुमान।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर, भारत को अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप वित्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने संस्थागत ढांचे में बदलाव की जरूरत होगी। भौतिक, सामाजिक और डिजिटल अवसंरचना, कौशल, हरित ऊर्जा, नवोन्मेषी विनिर्माण और एमएसएमई के वित्तपोषण पर जोर दिया जाएगा। इसके मूल में पर्याप्त द्वितीयक बाजार व्यापार चलनिधि और विस्तार के साथ एक मजबूत कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार होना चाहिए। बाहरी वित्तपोषण निवेश को बढ़ावा देने और नई प्रौद्योगिकियों को लाने में तेजी से जीवंत भूमिका निभाएगा, बशर्ते बाहरी वित्तपोषण के संबंध में अवशोषण क्षमता निर्यात क्षमता को बढ़ाने और लएफडीआई को आकर्षित करने वाले सुधारों की खोज के साथ बढ़े। विकास के उच्च स्तर की भारत की खोज में, वित्तपोषण को एक सुविधाकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक अवरोधक के रूप में। जैसा कि केंद्रीय बैंकिंग के मूल सिद्धांत के प्रवर्तक वाल्टर बेजहोट ने अपने लोम्बार्ड स्ट्रीट में लिखा है, 'जितना कम पैसा बेकार पड़ा रहेगा, उतना ही अधिक लाभांश होगा'।[30] वित्त और विकास के बीच संबंधों पर जहां से मैंने शुरुआत की थी, वहीं पर लौटते हुए, मैं स्वर्गीय आनंद चंदावरकर को उद्धृत करने से बेहतर कुछ नहीं कर सकता, जो आरबीआई में अर्थशास्त्र के पेशे के साधकों की पवित्र परंपरा के सबसे अच्छे समर्थकों में से एक हैं[31]: "इस संबंध में बहस कि क्या वित्तीय मध्यस्थता और विकास एक "मांग-अनुसरण" या "आपूर्ति-अग्रणी" घटना है, तुलनात्मक रूप से इस प्रश्न का पूरक है: कि क्या (देशों) के पास उचित नीतियां अपनाने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि और आर्थिक राजनीति है?"

धन्यवाद।

[30] बेजहोट, वाल्टर, 1873, लोम्बार्ड स्ट्रीट: ए डिस्क्रिप्शन ऑफ़ द मनी मार्केट, न्यूयॉर्क: स्क्रिब्नर, आर्म्सटोंग एंड कंपनी.

[31] चंदावरकर, ए., विकास के लिए वित्त कितना प्रासंगिक है?, आईएमएफ ई-लाइब्रेरी, https://www.elibrary.imf.org >article-A004-en. जगदीश भगवती ने आनंद चंदावरकर को "अपने आप में एक अलग श्रेणी का व्यक्ति, एक पुस्तक प्रेमी, एक बुद्धिजीवी, एक प्रतिभाशाली लेखक और एक बेहतरीन अर्थशास्त्री बताया, और यह सब बिना किसी अहंकार के और बहुत ही शालीनता और आकर्षण के साथ।"